

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून:दिनांक: 6 मार्च, 2009

विषय:—पासपोर्ट कार्यालय देहरादून के लिए भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-167/12-ए-20(2008-11)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक-14.01.09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम नत्थनपुर तहसील सदर जिला देहरादून में खसरा संख्या-309मि0 रकबा 0.1044 एवं खसरा संख्या-313क मि0 रकबा 0.1550 अर्थात् कुल रकबा 0.2594 है0 भूमि जो वर्तमान में खाली है, एवं श्रेणी-4(अ) अतिरिक्त घोषित सीलिंग भूमि है, को पासपोर्ट कार्यालय देहरादून हेतु प्रचलित बाजार की दर से भूमि की कीमत वसूल किये जाने के अतिरिक्त मालगुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि मालगुजारी के पूंजीकृत मूल्य के रूप में वसूल करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

- (6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दुसंख्या- 1 से 5 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

|
(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ०प०सं०- 212 /संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय देहरादून।
4. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।